(b) if the answer to the part (a) above be in the negative whether there is any proposal under Government's consideration for setting up of such institutions there and if so, by when the same is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARI KRISHNA SHASTRI): (a) None, Sir.

(b) The Indian Council of Agricultural Research has sanctioned a research proposal on Citrus in Nimar Valley under National Agricultural Research Project (NARP). Another proposal for supporting research programme on Citrus in Satpura Plateau under cess fund programme is under consideration of the Council.

Exploitation of vegetables and fruits growers in Madhya Pradesh

3071. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that vegetabeles and fruits growers of Madhya Pradesh get only one fourth of the price paid by the consumers of their produce resulting their exploitation and it also discourage them to cultivate these crops; and

(b) if so, what measures are being take to provide marketing facilities and fixation of reasonable prices of their crops?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) There is no report from the State Government that vegetables and fruits growers of Madhya Pradesh get only one fourth of the price paid by the consumers of their produce and thereby affecting cultivation of these crops.

राज्यों को तिलहन के बीजों की आपूर्ति

3072. **श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न राज्य सरकारें राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना लागू कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे राज्यों को वांछित किस्म के बीज यथा-समय मिल जायें, क्या उपाय किए है,

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्यों में तिलहन बीज की अनुपलब्धता के कारण 1987 की खरीफ की फसल में तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार कोई अधिनियम पारित कर ऐसी नीति अपनाने का विचार रखती है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विभिन्न राज्यों से बीज एकत्रित कर समस्त राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार यथासमय बीज उपलब्ध करायेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित राज्यों को यह सलाह दी गई है कि व 'प्रजनक बीजों' के लिए अपने मांग पत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को बुआई के समय से एक वर्ष पहले भेजा करें ताकि राज्य बीज निगमों, राज्यों के विभागीय फार्मों द्वारा शुरु किए जाने आधारी और प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रजनक बीजों का उत्पादन किया जा सके । इससे राज्य स्तर पर किसानों की मांगों को पूरा कर सकेंगे ।

(ग) 1987 के दौरान खरीफ की तिलहनों का उत्पादन अधिकांश तिलहन उत्पादक राज्यों में पड़े व्यापक सूखे के कारण प्रभावित हुआ था न कि बीज उपलब्ध न होने की वजह से ।

(घ) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।